

क्या नगर निगम प्रत्याशी होने के लिए प्रॉपर्टी डीलर, दलाल, शराब माफ़िया या राजनीतिक चापलूस होना जरूरी है?

यदि नहीं तो नगर निगम, फरीदाबाद में कुछ सीटों को छोड़ कर अधिकांश पर इन्हीं लोगों का वर्चस्व क्यों है?

लंबे समय से कई बार स्थानीय विधायकों का हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहने के बावजूद फरीदाबाद में जन सुविधायें और आम व्यवस्था पूर्णतया चरमरा चुकी है।

नतीजतन, यहां का आम आदमी पूरी तरह से असहाय और बदहाली के मुहाने पर खड़ा दिन-रात आंसू बहाने के लिए मजबूर है। दूसरी ओर, राजनीतिक दलाल और चापलूस धवल सफ़ेद कुर्ते पहन कर टवेरा, क्लासिक और मर्सीडीज जैसी बेशकीमती गाड़ियों की शोभा बढ़ा रहे हैं।

चुनाव के दिनों में दीवारों पर लगे लाखों के होर्डिंग क्या दो नंबरी दौलत का फूहड़ प्रदर्शन नहीं हैं? घरों की दीवारों पर मकान मालिकों की मर्जी के बगैर चिपकाये गये लाखों रंगीन पोस्टर क्या जनविरोधी और गैरकानूनी नहीं हैं। हमारा अंधा और नाकारा प्रशासन अगर इस सब की ओर से आंखें मूंदे खड़ा है तो फिर यह कानून और खर्च सीमायें तय ही क्यों गई हैं?

इस बहती गंगा में 'चोर को मोर' वाली कहावत भी रंग दिखा रही है। चुनाव प्रचार के होर्डिंग या फ्लैक्स बोर्ड बनाने वाले सैंकड़ों प्रत्याशियों से दुगने-चौगुने दाम एडवांस ले कर उन्हें चक्कर कटवा रहे हैं। प्रचार के लिए ऑडियो कैसेट सीडी बनाने वाली एक फ़र्म ने एक स्थानीय दुकानदार के माध्यम से लाखों रुपये बटोरे और रफ़ूचकर हो गई। लोगों को दिन-रात घुमाने वाले प्रत्याशी भी इन चुनावखोरों के शिकार हो चुके हैं और कुछ भी खास करने की स्थिति में नहीं हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा के प्रसार और सूचना प्रणाली के विकास के साथ आम नागरिकों का एक छोटा-सा तबका कुछ ज्यादा सजग और चिंतित दिखाई देता है। अच्छा लगता है जब बहुत से लोग कहते हैं कि यदि वार्ड के दर्जनों प्रत्याशियों में एक भी हमारे वोट का हकदार न हो तो जायें तो जायें कहां?

किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार करना हमारी और हमारे समाचार पत्र की नीतियों के अनुरूप नहीं है। परंतु यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने पिछले 35 सालों में किये गये कामों के आधार पर एक 'रोल मॉडल' के समान हो जाये तो हमारी कलम उसके व्यक्तित्व को जनता के सामने सही तरीके से पेश करने में गुरेज़ नहीं करेगी, क्योंकि यह स्वयं उसका अपना अर्जित किया गया हक है, अधिकार है। संयोगवश यह व्यक्ति नगर निगम चुनावों में प्रत्याशी भी हो तो भी इसकी सही तस्वीर को जनता के सामने पेश करना हमारा फर्ज़ है।

वार्ड नंबर-26 के 15 प्रत्याशियों की भीड़ में प्रोफ़ेसर सत्यपाल फ़ौगाट की कार्यशैली उनकी दमदार विचारधारा और आदर्श चरित्र की तस्वीर पेश करती है। वार्ड 26 के वोटरों के सामने बहुत से सवाल हैं।

1. जहां बाकी के प्रत्याशियों ने वार्ड की दीवारों को पोस्टरों और होर्डिंगों से नेस्तनाबूद कर दिया है, वहां प्रोफ़ेसर फ़ौगाट अभी तक कहीं एक भी होर्डिंग और पोस्टर पर दिखाई नहीं देते।

2. जहां वार्ड नं. 26 के अधिकतर प्रत्याशी हज़ारों लोगों के खाने-पीने का इंतजाम दिल खोलकर कर रहे हैं, वहां प्रोफ़ेसर फ़ौगाट की ओर से किसी मामूली लंगर की सूचना भी नहीं मिली है।

3. ऐसा सुनने में आया है कि वार्ड नं. 26 में प्रोफ़ेसर फ़ौगाट ही एकमात्र प्रत्याशी हैं जिन्होंने वार्ड के लगभग हर घर में जा कर एक-एक वोटर से सीधा संवाद करने की पहल की है।

4. प्रोफ़ेसर सत्यपाल फ़ौगाट और उनके प्रतिनिधियों जिनमें अधिकतर साथी प्रोफ़ेसर और युवा वर्ग हैं, ने प्रोफ़ेसर फ़ौगाट के लिए वोट मांगने की बजाये उन मापदंडों पर बात की है जिन्हें सामने रख कर वोट देने का फ़ैसला किया जाये।

5. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के टॉपर और एक आदर्श शिक्षक प्रोफ़ेसर फ़ौगाट एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव



आचार संहिता का सख्ती से पालन किया है और करेंगे।

6. यह भी चर्चा है कि यदि एक प्रोफ़ेसर भी जीत कर निगम में पहुंचने में सफल हो गया तो यह न सिर्फ़ एक नई शुरुआत होगी, बल्कि समय का एक नया मोड़ होगा जिससे पार्षद पद का सम्मान और अर्थ एक नई बुलंदी हासिल कर सकेगा। हमारे संवाददाता के कुछ प्रश्नों के उत्तर में प्रोफ़ेसर सत्यपाल फ़ौगाट ने कहा - चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया में सबसे पहली पर्ची 'चढ़ता सूरज' मेरे नाम आई तो बेसाख्ता कुछ लोगों के मुंह से निकल पड़ा, प्रोफ़ेसर साहब पहली लड़ाई तो आपने जीत ली।

प्रोफ़ेसर फ़ौगाट ने आगे कहा कि मैं बिना नतीजों की परवाह किये अपना चुनाव अभियान आचार संहिता के दायरे में रह

कर लड़ूंगा और यकीनन यह एक पैगाम बन कर घर-घर तक जाएगी।

यदि आप भगवान, ईसानियत और कर्मों पर भरोसा रखते हैं तो बिना भ्रष्ट तरीके अपनाए आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं। प्रोफ़ेसर से जब पूछा गया कि आप जीत गये तो नया क्या होगा? उन्होंने कहा कि मेरा चढ़ता सूरज एक नया सवेरा लेकर आएगा जिसमें आम आदमी को पूरा सम्मान मिलेगा। अधिकतर प्रचार वाहनों पर अचानक देशभक्ति के गीतों के शोर पर टिप्पणी करते हुए प्रो. सत्यपाल फ़ौगाट ने कहा, 'पढ़ने-लिखने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई में खलल डाल कर वोट हासिल करने का गुनाह एक अध्यापक या पिता भला कैसे कर सकता है।'

समाज सेवा : सेवा या धंधा?

समाज सेवा शुरू से ही एक महंगा सौदा रहा है। पहले धनी लोग ही समाज सेवा करते थे, धर्मशालायें बनवाते थे, कुएं खुदवाते थे, गरीब लोगों के लिए लंगर चलवाते थे और पुण्य कमाते थे। अपना परलोक सुधारने के लिए इहलोक में अपना धन खर्च करते थे, पानी के प्याऊ लगाते थे, श्मशान घाट पर सेवा करते थे। आवारा पशुओं को खाना खिलाते थे। अपनी हैसियत के हिसाब से हर कोई समाज सेवा करता था। आज समाज सेवा ने एक विशाल रूप ले लिया है। गरीब तो अपनी उसी सेवा में लगे हुए हैं, पर धनी लोग अपना अपना इहलोक और सुधारने के लिए समाज सेवा में उतर गये हैं। ये लोग अपने घर से लाखों-करोड़ों खर्च कर के संसद, विधान सभा और नगर निगम के चुनाव लड़ कर उसका सदस्य बन कर समाज सेवा करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि समाज सेवा एक जुनून की तरह इन पर सवार हो गई है। ये

किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते चाहे इसके लिए इन्हें मारपीट, सांप्रदायिकता, गुंडागर्दी, शराब और गुंडों का सहारा क्यों न लेना पड़े। धन्य है समाज सेवा की यह भावना।

फरीदाबाद नगर निगम के चुनावों की घोषणा होने के बाद सैंकड़ों समाजसेवी अपनी बिलों से बाहर आ गये हैं। और साम-दाम-दंड-भेद, सभी उपाय अपना कर समाज सेवा का पुण्य कार्य अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ये लोग अपना परलोक नहीं अपितु इहलोक अधिक मजबूत करना चाहते हैं। और जो लोग एक बार पार्षद रह चुके हैं, वो तो किसी तरह इस पुनीत कार्य को हाथ से जाने देना नहीं चाहते। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों से मिलने वाले अवैध धन के धंधे से प्रेरणा ले कर और पूर्व पार्षदों की हरियाली देख कर ही अधिकांश उम्मीदवारों ने पार्षद बन कर समाज सेवा का प्रण लिया है। कई समाज सेवक तो मय परिवार के इसे करना चाहते हैं। यदि उनका वार्ड

महिला आरक्षित हो जाये तो वे मां, पत्नी, भाभी, बहू, पतोहू को पार्षद बनाने के लिए मैदान में उतर गये हैं। एक निवर्तमान पार्षद का मत था कि या तो राजनीति में चरित्रहीन महिलायें आती हैं या राजनीति में आ कर उनका चरित्र बिगड़ जाता है। लेकिन जब उनका वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है तो उन्होंने अपनी पत्नी का नामांकन भरवा दिया है। पता नहीं, उनकी पत्नी पहले से बिगड़ी है या ये खुद उसे बिगाड़ना चाहते हैं।

समाज सेवा के इस जुनून में पिछले एक वर्ष से ये अपने वार्ड के मतदाताओं को फ्लेक्स के बोर्डों के जरिये बधाई देने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते। ये तो भला हो फ्लेक्स बोर्ड बनाने वाली मशीनों का कि आदमी सस्ते में समाज सेवक बन जाता है। वरना एक निवर्तमान पार्षद का पति एक फ़ोटो वाला बोर्ड बनाने के लिए पंद्रह से बीस हज़ार ले लेता था। अब यही काम 1000 से 1200 रुपयों के बीच हो जाता है।

बकाया वेतन के भुगतान के लिए

ईएसआई के अस्थाई कर्मचारी संघर्षरत

फरीदाबाद (नगेन्द्र मनराल) ईएसआई अस्पतालों तथा उनसे संबद्ध विभिन्न डिस्पेंसरियों में ठेकेदारी के तहत नियुक्त 100 से अधिक कर्मचारी अपने सात माह के बकाया वेतन भुगतान की मांग को ले कर 1 मई से संघर्षरत हैं। ये कर्मचारी ईएसआई अस्पताल नंबर-3 तथा उससे संबद्ध पांच नंबर स्थित डिस्पेंसरी नं. 3, नंबर चार स्थित डिस्पेंसरी नं. 3, नंबर चार स्थित डिस्पेंसरी नं. 1, नंबर दो स्थित डिस्पेंसरी नं. 5 एवं जवाहर कालोनी स्थित डिस्पेंसरी नं. 6 तथा सेक्टर-8 स्थित ईएसआई अस्पताल एवं उससे संबद्ध सेक्टर-7, सेक्टर-19 तथा तिगांव स्थित डिस्पेंसरियों में कार्यरत हैं।

ये कर्मचारी 24 अप्रैल, 2008 को शर्मा एसोशियेट नामक ठेकेदारी फर्म के मार्फत भर्ती हुए। शर्मा एसोशियेट का डेढ़ वर्ष का ठेका था। इस दौरान शर्मा एसोशियेट ने इन कर्मचारियों को कोई पी.एफ. नंबर नहीं दिया और न ही इनका ईएसआई काटा। उसने इन कर्मचारियों का तीन माह (अगस्त,

सितंबर, अक्टूबर) का वेतन भी नहीं दिया। नवंबर में ये कर्मचारी श्री श्याम इंटरप्राइजेज, द्वारका प्लेस, दुकान संख्या 120, फरीदाबाद के अंतर्गत पुनः नियुक्त हुए। इस फर्म द्वारा भी वर्ष 2009 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई माह का वेतन इन कर्मचारियों को नहीं दिया गया। कुल मिला कर इन दो ठेकेदारी फर्मों के अंतर्गत काम करते हुए इन कर्मचारियों का सात माह का वेतन तथा दो साल का पी.एफ. का पैसा अभी तक नहीं मिला है। इन कर्मचारियों को न तो पी.एफ. का नंबर दिया गया है और न ही कोई अन्य रिकार्ड।

कर्मचारियों के अनुसार शर्मा एसोशियेट ने शुरू में 2000 रुपया बतौर सिक्यूरिटी के जमा कराये थे तो श्याम इंटरप्राइजेज ने 500 रुपये की सिक्यूरिटी जमा कराई थी। यह पैसा इन दोनों ठेकेदारी फर्मों द्वारा आज तक वापस नहीं किया गया है। सिक्यूरिटी के नाम पर धन इसलिए जमा कराया जाता है कि ताकि ठेकेदार की ठेका अवधि खत्म

होने के पहले ही कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ कर न जा सके। इस तरह से यह यह सूक्ष्म स्तर पर बंधुआ मजदूरी का ही एक रूप है। कर्मचारियों ने जब ठेकेदारों द्वारा वेतन भुगतान न करने की शिकायत ईएसआई अस्पताल नंबर-3 के चिकित्साधिकारी ए.के.शर्मा से की तो इन कर्मचारियों से सहानुभूतिपूर्वक पेश आने की बजाय वे इनकी छंटनी करने तथा अगले ठेके में नहीं रखने की धमकी देने लगे।

आखिरकार ठेकेदार की ठगी और ईएसआई के नौकरशाह अधिकारियों के असंवेदनशील व्यवहार से दुखी हो कर इन कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ी। कर्मचारियों का यह आंदोलन ईएसआई नंबर-3 में धरने के रूप में बदस्तूर जारी है। इससे पूर्व इन कर्मचारियों ने मार्च में तीन दिन तथा अप्रैल में दो दिन का धरना दिया था, लेकिन ईएसआई प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। ईएसआई के इन अस्थाई कर्मचारियों का आंदोलन देख कर पहले तो ईएसआई के अफ़सरान ने इन

कर्मचारियों को डराने-धमकाने से लेकर लालच देने तथा सब तरह के हथकंडों का प्रयोग किया एवं आंदोलन से हटने के लिए एक-एक को पकड़ कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया। आंदोलनरत कर्मचारियों में से जिनके माता-पिता ईएसआई में कार्यरत हैं, उनके माता-पिता को धमकाने व उनका स्थानांतरण करने की धमकी देने जैसी कार्यवाहियां ईएसआई के अफ़सरानों द्वारा की गईं। लेकिन इन धमकियों से आंदोलनरत कर्मचारियों का उत्साह कम होने के बजाय बढ़ता गया और वे दृढ़तापूर्वक संघर्ष के मैदान में डटे रहे।

10 मई को आंदोलनरत कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ, सीटू व इंकलाबी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ चिकित्साधिकारी के कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन व नारेबाजी की। चिकित्साधिकारी कर्मचारी नेताओं से बात करने पर मजबूर हुए। बातचीत में चिकित्साधिकारी ने कुछ सरकारी अडचनों व बाधाओं की बात करते हुए

यथाशीघ्र बकाये वेतन के भुगतान का आश्वासन दिया। बहरहाल, ईएसआई कर्मचारियों का धरना जारी है।

गौरतलब है कि ये कर्मचारी दवा बांटने, पर्ची बनाने से लेकर स्टॉफ नर्स तक का काम करते हैं। जहां छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के बाद डॉक्टरों एवं अन्य स्थाई कर्मचारियों के वेतन में कल्पनातीत वृद्धि हुई है, वहीं अधिकाधिक काम ठेकेदारी के तहत कर्मचारी नियुक्त करके करवाये जा रहे हैं। ठेकेदारी के अंतर्गत नियुक्त ये कर्मचारी स्थाई कर्मचारियों से अधिक काम करते हैं, डॉक्टरों व अफ़सरों की फटकार झेलते हैं तथा न्यूनतम वेतन भी जो इन्हें दिया जाता है, उसे पाने के लिए इन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाया पड़ रहा है। नयी आर्थिक नीति के सरकारी क्षेत्र पर पड़ने प्रभाव अथवा निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों का सार्वजनिक क्षेत्र पर कुप्रभाव को ईएसआई अस्पताल के इन आंदोलनरत कर्मचारियों की दुर्दशा को देख कर समझा जा सकता है।